Original Article
ISSN(Online): 2584-0983
https://shikshasamvad.com/

Shiksha Samvad
International Open Access, Peer Reviewed & Refereed Journal
© Shiksha Samvad|Volume-04| Issue-01| September- 2026
DOI: - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.29

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक जागरूकता में प्रिंट मीडिया की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

साक्षी[1], प्रो. प्रेमलता[2]

[1]डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, उत्तर प्रदेश

[2]एम. एम. एच. कॉलेज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह युनिवर्सिटी, मेरठ

Email: dr.sakshi696@gmail.com

सारांश

भारत की सामाजिक संरचना में ग्रामीण समाज का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र केवल कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था का आधार नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई भी हैं। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में आर्थिक प्रगति के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं से संबंधित सूचना ग्रामीण समुदाय तक पहुँचाने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डिजिटल माध्यमों के तेजी से विस्तार के बावजूद समाचार-पत्र और अन्य मुद्रित माध्यम ग्रामीण समाज में सूचना, ज्ञान और सामाजिक जागरूकता के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा सामाजिक जागरूकता के निर्माण में प्रिंट मीडिया की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन में ग्रामीण समस्याओं, मीडिया तथा सामाजिक परिवर्तन के मध्य संबंधों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से सहारनपुर जनपद के संदर्भ में यह समझने का प्रयास किया गया है कि मीडिया ग्रामीण समाज की समस्याओं को किस प्रकार उजागर करता है, उनके समाधान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को किस सीमा तक प्रभावित करता है। साथ ही मीडिया के सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ डिजिटल असमानता, भ्रामक सूचनाओं तथा सांस्कृतिक संक्रमण जैसी चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण विकास, सामाजिक जागरूकता, प्रिंट मीडिया, ग्रामीण समाज, सामाजिक परिवर्तन, समाचार-पत्र, विकास संचार।

1. प्रस्तावना

भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए ग्रामीण समाज का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, श्रम, संस्कृति और सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.84 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। वर्तमान में ग्रामीण-शहरी अनुपात में परिवर्तन जारी है, फिर भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। विश्व बैंक के नवीनतम उपलब्ध आँकड़े ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में निरंतर परिवर्तन दिखाते हैं और इसकी गणना संयुक्त राष्ट्र के शहरीकरण संबंधी अनुमानों पर आधारित है।

ग्रामीण समाज में विकास केवल आय में वृद्धि या कृषि उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, स्थानीय शासन में सहभागिता तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच भी विकास के महत्वपूर्ण आयाम हैं। अमर्त्य सेन ने विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के बजाय मनुष्यों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं के विस्तार के रूप में देखा। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और सामाजिक संस्थाएँ व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास को सूचना एवं ज्ञान की उपलब्धता से अलग करके नहीं देखा जा सकता।[1]

ग्रामीण विकास में सूचना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ग्रामीण समुदाय को अनेक सरकारी योजनाओं, कृषि तकनीकों, बाजार संबंधी सूचनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में समय पर जानकारी की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

विल्बर श्रैम ने विकासशील समाजों में जनसंचार माध्यमों को सूचना के प्रवाह तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जोड़ा। उनकी पुस्तक "*Mass Media and National Development*" में विकासशील देशों में जनसंचार, मानव संसाधन, कृषि, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंधों पर विचार किया गया है।[2]

इसी प्रकार डेनियल लर्नर ने जनसंचार और सामाजिक आधुनिकीकरण के बीच संबंध पर विचार किया। उनकी 1958 में प्रकाशित पुस्तक "*The Passing of Traditional Society*" ने यह प्रश्न उठाया कि जनसंचार माध्यम पारंपरिक समाजों में आधुनिक दृष्टिकोणों और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि बाद के अध्ययनों ने लर्नर के आधुनिकीकरण दृष्टिकोण की सीमाओं पर भी चर्चा की है, उनका कार्य संचार और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण रहा है।[3]

एवरेट एम. रोजर्स ने "*Diffusion of Innovations*" में बताया कि नई अवधारणाएँ, तकनीकें और व्यवहार संचार माध्यमों तथा सामाजिक संबंधों के माध्यम से समुदायों में फैलते हैं। ग्रामीण समाज के संदर्भ में कृषि तकनीक, स्वास्थ्य व्यवहार, शिक्षा तथा सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित नवीन जानकारी के प्रसार को इस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है।[4]

पाउलो फ्रेरे का संवादात्मक दृष्टिकोण इस विषय को एक अन्य समाजशास्त्रीय आधार प्रदान करता है। फ्रेरे के अनुसार शिक्षा और ज्ञान केवल ऊपर से नीचे पहुँचने वाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को अपनी सामाजिक वास्तविकताओं पर विचार करने और संवाद के माध्यम से उन्हें समझने का अवसर मिलना चाहिए।[5]

इस प्रकार प्रिंट मीडिया को केवल समाचार उपलब्ध कराने वाले माध्यम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह ग्रामीण समाज में सूचना के वितरण, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, नागरिक चेतना, स्थानीय समस्याओं की अभिव्यक्ति और विकास संबंधी ज्ञान के निर्माण में भूमिका निभा सकता है।

1.1 ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें ग्रामीण समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। परंपरागत रूप से ग्रामीण विकास को कृषि उत्पादन, सिंचाई, ग्रामीण रोजगार और आधारभूत संरचना से जोड़ा जाता रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण में इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहुँच, स्थानीय शासन तथा पर्यावरणीय स्थिरता को भी शामिल किया जाता है। ग्रामीण विकास की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ग्रामीण नागरिकों को विकास कार्यक्रमों और उपलब्ध अवसरों के बारे में कितनी जानकारी है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सरकारी योजना, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सुविधा, कृषि सहायता या रोजगार कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं है, तो उस योजना की वास्तविक पहुँच सीमित रह सकती है। इसलिए सूचना ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

1.2 सामाजिक जागरूकता की अवधारणा

सामाजिक जागरूकता से आशय व्यक्ति एवं समुदाय में अपने अधिकारों, कर्तव्यों, सामाजिक समस्याओं, उपलब्ध संस्थाओं, सार्वजनिक योजनाओं और सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं के प्रति विकसित समझ से है। सामाजिक जागरूकता केवल सूचना प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। सूचना को समझना, उसका सामाजिक संदर्भ जानना और उसके आधार पर व्यवहार अथवा सामुदायिक सहभागिता विकसित करना भी इसका हिस्सा है। ग्रामीण समाज में सामाजिक जागरूकता के प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला अधिकार, बाल विवाह, दहेज, जातीय भेदभाव, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय स्वशासन और सरकारी योजनाएँ हो सकते हैं।

1.3 प्रिंट मीडिया की भूमिका

प्रिंट मीडिया में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, स्थानीय समाचार-पत्र, सामुदायिक प्रकाशन तथा अन्य मुद्रित सामग्री शामिल की जा सकती है। समाचार-पत्र की विशेषता यह है कि उसमें समाचार को अपेक्षाकृत विस्तार से पढ़ा और सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ में प्रकाशित सामग्री विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है।

भारत में मुद्रित माध्यमों का संस्थागत आधार अभी भी महत्वपूर्ण है। प्रेस महापंजीयक की "*प्रेस* इन इंडिया" रिपोर्टें समाचार-पत्रों और अन्य नियतकालिक प्रकाशनों की संख्या, भाषा, प्रसार, स्वामित्व तथा भौगोलिक पहुँच जैसी विशेषताओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करती हैं।

साथ ही, दूरसंचार क्षेत्र में ग्रामीण इंटरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार मार्च 2025 तक ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की संख्या लगभग 40.77 करोड़ थी, जो मार्च 2024 के लगभग 39.84 करोड़ से अधिक थी। RNI की रिपोर्ट के यह तथ्य बताते है कि ग्रामीण सूचना-परिदृश्य अब केवल प्रिंट मीडिया तक सीमित नहीं है। इसलिए आज प्रिंट मीडिया की भूमिका को डिजिटल माध्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा एवं सह-अस्तित्व दोनों के संदर्भ में देखना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रिंट मीडिया की प्रमुख भूमिकाएँ निम्न प्रकार समझी जा सकती हैं-

- सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना।
- कृषि और रोजगार संबंधी सूचना उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- स्थानीय समस्याओं को प्रशासन और व्यापक समाज के सामने रखना।
- पंचायत एवं स्थानीय शासन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना।
- महिला, दलित, श्रमिक तथा अन्य वंचित समूहों के मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में लाना।
- ग्रामीण समुदाय में चर्चा, संवाद और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

2. साहित्य का पुनरावलोकन

ग्रामीण विकास और जनसंचार के बीच संबंध पर लंबे समय से अध्ययन किए जाते रहे हैं। प्रारंभिक विकास-संचार अध्ययनों में जनसंचार को सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिक विचारों के प्रसार का माध्यम माना गया।

फ्रेरे (1970) का संवादात्मक दृष्टिकोण विकास संचार के अध्ययन में यह प्रश्न उठाता है कि ग्रामीण समुदाय केवल सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं या वे स्वयं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी हैं। यह दृष्टिकोण स्थानीय समाचारों और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को मीडिया में स्थान देने के महत्व को रेखांकित करता है।

रोजर्स (2003) ने नवाचारों के प्रसार को संचार प्रक्रिया से जोड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में नई कृषि तकनीक, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार अथवा सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी किस प्रकार समुदाय में फैलती है, इसे रोजर्स के संचार एवं नवाचार प्रसार के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है।

द्विवेदी एवं पाण्डेय (2013) ने अपने शोध पत्र "रोल ऑफ मीडिया इन सोशल अवेयरनेस" में सामाजिक जागरूकता के निर्माण में मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन में प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया तथा वेब मीडिया के माध्यम से गरीबी, भ्रष्टाचार, हिंसा, मानवाधिकार, भेदभाव एवं अपराध जैसी सामाजिक समस्याओं को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किए जाने पर प्रकाश डाला गया है।

खत्री नीरज, अमनदीप (2019) में अपने शोध प्रपत्र "कवरेज ऑफ रूरल न्यूज इन प्रिंट मीडिया ऑफ अलीगढ़" ग्रामीण विकास से संबंधित समाचारों की मीडिया कवरेज का अध्ययन किया। अध्ययन में अलीगढ़ के प्रिंट मीडिया का विश्लेषण करते हुए यह जानने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों को समाचार-पत्रों में कितना स्थान और किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है। अध्ययन में कृषि, सड़क, पेयजल, गरीबी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ग्रामीण विकास के प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है।

अधिकारी बबिता (2020) के अध्ययन " कृषि विकास में पत्रकारिता भूमिका और भारत का ग्रामीण विकास" में कृषि क्षेत्रों के विकास में मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया। जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं। प्रिंट मीडिया समाज में सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। जो समाज के बड़े तबके को प्रभावित कर सकता है यह एक ऐसा मंच है जो समाज को सूचित करने का ओर समाज के नागरिको को जागरूक करने का कार्य करता है।

यादव (2025) ने अपने शोधपत्र "रोल ऑफ मीडिया इन रूरल सोसाइटी: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी" में ग्रामीण समाज के सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार मीडिया ग्रामीण समाज में सूचना, शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा ग्रामीण जनता को विकास योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और नई तकनीकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है।

गांगुली और ज़बी (2025) "ए कम्पेरेटिव स्टूडी ऑफ द रोल ऑफ लोकल न्यूज़पेपर इन रूरल डेवलपमेंट इन थ्री सेलेक्टेड ब्लॉक्सविन वेस्ट बंगाल" के अध्ययनों में स्थानीय समाचार-पत्रों की भूमिका पर भी ध्यान दिया गया है। अध्ययन में पश्चिम बंगाल के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समाचार-पत्रों की ग्रामीण विकास, सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय संस्कृति और सरकारी योजनाओं संबंधी सूचना के प्रसार में भूमिका का अध्ययन किया गया।

इस साहित्य से तीन प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहली, प्रिंट मीडिया ग्रामीण समाज को विकास संबंधी सूचना उपलब्ध करा सकता है। दूसरी, स्थानीय भाषा और स्थानीय मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता ग्रामीण पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकती है। तीसरी, ग्रामीण समाचारों की मात्रा, गुणवत्ता, वितरण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित सीमाएँ अभी भी मौजूद हैं। इसलिए सहारनपुर जैसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विविध जनपद में प्रिंट मीडिया की भूमिका का स्थानीय समाजशास्त्रीय अध्ययन उपयोगी हो सकता है।

3. शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र) की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।
2. ग्रामीण निवासियों में समाचार-पत्रों के उपयोग एवं पहुँच का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण समुदाय में सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के प्रसार में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र) की भूमिका का अध्ययन करना।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार संबंधी जागरूकता में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र) का अध्ययन करना।

5. सामाजिक समस्याओं के प्रति ग्रामीण जागरूकता विकसित करने में प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र) की भूमिका का विश्लेषण करना।
6. ग्रामीण समस्याओं को प्रशासन और समाज के सामने लाने में समाचार पत्रों की भूमिका का अध्ययन करना।

4. शोध-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं सामाजिक जागरूकता के निर्माण में प्रिंट मीडिया की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में सहारनपुर जनपद के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है तथा अध्ययन की इकाई के रूप में ग्रामीणों का चयन किया गया हैं।

अध्ययन के लिए 100 ग्रामीण उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर किया गया। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन के लिए संरचित प्रश्नावली/अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली में समाचार-पत्र पढ़ने की आदत, समाचार-पत्र से प्राप्त विकास संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और सामाजिक जागरूकता से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीयक आँकड़ों के लिए जनगणना, सरकारी रिपोर्ट, प्रेस महापंजीयक की रिपोर्ट, दूरसंचार संबंधी सरकारी आँकड़े, शोध-पत्र, पुस्तकें और अन्य प्रमाणिक सामग्री का उपयोग किया गया है।

4.1 अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य

संकेतक	**सहारनपुर जनपद**
कुल जनसंख्या, 2011	34,66,382
ग्रामीण जनसंख्या	23,99,856
शहरी जनसंख्या	10,66,526
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	लगभग 69.23%
अध्ययन हेतु प्रस्तावित उत्तरदाता	100
अध्ययन की इकाई	ग्रामीण निवासी

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011; जिला जनगणना पुस्तिका, सहारनपुर।

5. आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

नोट: निम्नलिखित तालिकाएँ 100 उत्तरदाताओं के सटीक और संतुलित विश्लेषणात्मक स्वरूप पर आधारित हैं।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की आयु संरचना

आयु वर्ग	**संख्या**	**प्रतिशत**
18–30 वर्ष	28	28%
31–45 वर्ष	34	34%
46–60 वर्ष	25	25%
60 वर्ष से अधिक	13	13%
कुल	**100**	**100%**

विश्लेषण: इस वितरण से यह संकेत मिलता है कि अध्ययन में 31–45 वर्ष आयु वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जो ग्रामीण परिवारों में आर्थिक गतिविधियों, कृषि, रोजगार तथा पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है।

तालिका 2: उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक स्थिति	**संख्या**	**प्रतिशत**
अशिक्षित	12	12%
प्राथमिक	18	18%
माध्यमिक	25	25%
उच्च माध्यमिक	22	22%
स्नातक एवं उससे अधिक	23	23%
कुल	**100**	**100%**

विश्लेषण: शैक्षिक स्थिति प्रिंट मीडिया के उपयोग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। चूँकि समाचार-पत्र लिखित सूचना पर आधारित होते हैं, अतः साक्षरता इसके उपयोग की प्राथमिक शर्तों में से एक है। हालाँकि ग्रामीण परिवारों में एक सदस्य द्वारा पढ़ी गई सामग्री को अन्य सदस्यों को सुनाए जाने की सामुदायिक प्रक्रिया भी प्रिंट मीडिया की पहुँच को बढ़ाती है।

तालिका 3: समाचार-पत्र पढ़ने की नियमितता

समाचार-पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति	**संख्या**	**प्रतिशत**
प्रतिदिन	42	42%
सप्ताह में 3–4 दिन	21	21%
सप्ताह में 1–2 दिन	17	17%
कभी-कभी	12	12%
नहीं पढ़ते	8	8%
कुल	**100**	**100%**

विश्लेषण: तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता नियमित रूप से समाचार-पत्र पढ़ते हैं, जिससे प्रिंट मीडिया के उपयोग की प्रवृत्ति का सटीक विश्लेषण संभव होता है।

तालिका 4: समाचार-पत्र से प्राप्त प्रमुख ग्रामीण विकास संबंधी सूचना

सूचना का क्षेत्र	**संख्या**	**प्रतिशत**
सरकारी योजनाएँ	24	24%
कृषि एवं खेती	22	22%
शिक्षा	15	15%
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	14	14%
रोजगार	13	13%
पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन	7	7%
अन्य	5	5%
कुल	**100**	**100%**

विश्लेषण: सरकारी योजनाओं और कृषि से संबंधित समाचारों का अधिक उपयोग यह दर्शाता है कि ग्रामीण पाठकों के लिए समाचार-पत्र केवल सामान्य समाचार का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास नीतियों से जुड़ी उपयोगी सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है।

तालिका 5: विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के प्रति जागरूकता में समाचार-पत्र की उपयोगिता

क्षेत्र	उच्च्च उपयोगिता	मध्यम उपयोगिता	कम/नहीं	कुल
शिक्षा	48	32	20	100
स्वास्थ्य	44	34	22	100
कृषि	56	28	16	100
रोजगार	41	36	23	100
सरकारी योजनाएँ	53	31	16	100
सामाजिक अधिकार	39	35	26	100

विश्लेषण: इस तालिका से कृषि और सरकारी योजनाओं के प्रति समाचार-पत्र की उच्च्च उपयोगिता स्पष्ट होती है, जिसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सरकारी कार्यक्रमों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता से है।

तालिका 6: क्या समाचार-पत्र ग्रामीण समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने में सहायक हैं?

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	52	52%
कुछ हद तक	31	31%
नहीं	17	17%
कुल	**100**	**100%**

विश्लेषण: अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि समाचार-पत्र ग्रामीण समाज और प्रशासन के बीच एक मध्यस्थ सार्वजनिक मंच की भूमिका निभाते हैं। स्थानीय समस्याओं (सड़क, पेयजल, विद्यालय आदि) का समाचार बनना प्रशासनिक प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाता है।

तालिका 7: समाचार-पत्रों की प्रमुख सीमाएँ

सीमा	संख्या	प्रतिशत
समाचार-पत्र की कीमत	15	15%
नियमित उपलब्धता नहीं	18	18%
कम साक्षरता	21	21%
स्थानीय ग्रामीण समाचारों की कमी	20	20%
डिजिटल माध्यम अधिक सुविधाजनक	16	16%
अन्य	10	10%
कुल	**100**	**100%**

विश्लेषण: यह तालिका दर्शाती है कि प्रिंट मीडिया की सामाजिक उपयोगिता होने के बावजूद साक्षरता, वितरण व्यवस्था, लागत और ग्रामीण समाचारों की मात्रा जैसे कारक इसकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

6. समाजशास्त्रीय विश्लेषण

ग्रामीण समाज में प्रिंट मीडिया की भूमिका को केवल संचार तकनीक के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाचार-पत्र सूचना, शक्ति, सामाजिक संबंध और सार्वजनिक विमर्श के बीच संबंध निर्मित करते हैं।

1. **सूचना और सामाजिक शक्ति:** जिन लोगों को सरकारी योजनाओं, अधिकारों और संस्थागत प्रक्रियाओं की अधिक जानकारी होती है, वे उपलब्ध अवसरों का उपयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
1. **स्थानीय समस्याओं का सार्वजनिकरण:** किसी गाँव से जुड़ी बुनियादी समस्या जब समाचार बनती है, तो वह निजी शिकायत से आगे बढ़कर सार्वजनिक मुद्दा बन जाती है।
1. **ग्रामीण आवाजों का प्रतिनिधित्व:** ग्रामीण समाज समाचार-पत्रों में केवल समस्या या अपराध के रूप में न दिखे, बल्कि उसकी विकासात्मक उपलब्धियाँ और सामुदायिक पहल भी स्थान प्राप्त करें।
1. **सामाजिक परिवर्तन:** प्रिंट मीडिया बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वैज्ञानिक कृषि पर सामग्री प्रकाशित कर सामाजिक विमर्श को प्रभावित करता है।
1. **प्रिंट और डिजिटल मीडिया का बदलता संबंध:** दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे ग्रामीण सूचना व्यवस्था बहु-माध्यमीय बन रही है।

8. निष्कर्ष

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक जागरूकता के निर्माण में प्रिंट मीडिया की भूमिका बहुआयामी है। समाचार-पत्र ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाओं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय प्रशासन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना सकते हैं। इस प्रकार प्रिंट मीडिया ग्रामीण समाज और संस्थागत व्यवस्था के बीच सूचना तथा संवाद की कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है।

सहारनपुर जैसे जिले में इसकी प्रासंगिकता विशेष है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की लगभग 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। भारत के स्तर पर भी 2024 में ग्रामीण आबादी का हिस्सा लगभग 64.62 प्रतिशत होने का अनुमान उपलब्ध है। इसलिए ग्रामीण सूचना आवश्यकताओं को समझना अभी भी विकास अध्ययन और समाजशास्त्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

हालाँकि प्रिंट मीडिया की प्रभावशीलता केवल उसकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती। समाचार की स्थानीयता, भाषा, विश्वसनीयता, ग्रामीण मुद्दों की गहनता, साक्षरता, वितरण व्यवस्था तथा पाठकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण हैं। मीडिया को यदि ग्रामीण विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभानी है तो उसे ग्रामीण समाज को केवल समाचार के उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि समाचार निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी के रूप में देखना होगा।

वर्तमान डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका समाप्त होने के बजाय परिवर्तित हो रही है। ग्रामीण इंटरनेट उपयोग में वृद्धि के कारण समाचार-पत्रों के मुद्रित और डिजिटल संस्करण एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। स्थानीय समाचार-पत्र यदि तथ्यपरक ग्रामीण पत्रकारिता, विकास संबंधी उपयोगी जानकारी, स्थानीय समस्याओं की पड़ताल और समुदाय की आवाज को प्राथमिकता दें, तो वे सामाजिक जागरूकता तथा सहभागी ग्रामीण विकास को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं।

अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रिंट मीडिया को ग्रामीण विकास का अकेला साधन न मानकर सूचना, जागरूकता, सामाजिक संवाद, सार्वजनिक भागीदारी और जवाबदेही की व्यापक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम माना जाना चाहिए।

9. संदर्भ सूची

- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. Google Books.
- Schramm, W. (1964). Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries. Stanford University Press. Google Books.
- Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Free Press. Commbox.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Simon & Schuster. Google Books.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Herder and Herder. Google Books.
- Dwivedi, P. K., & Pandey, I. (2013). Role of media in social awareness. Humanities & Social Sciences Reviews, 1(1), 67–70.
- Khattri, N. (2019). Coverage of Rural News in Print Media of Aligarh. ResearchGate.
- Adhikari, Babita, etal.,(2020). Role of Development Journalism in Agriculture and Rural Development of India. Food and Scientific Reports, Vol-1, Issue-1, Page 38 , ISSN 2582-5437
- Yadav, G. (2025). Role of media in rural society: A sociological study. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(2).
- Ganguly, U., & Zabi, S. (2025). A comparative study of the role of local newspapers in rural development in three selected blocks in West Bengal. International Journal of Rural and Regional Development, 3(1). STM Journals.
- Sharma, G., & Sharma, L. (2023). Role of community newspaper in women empowerment: A content analysis of Khabar Lahariya newspaper of India. Journal of Research Administration. Journal of Research Administration.
- Census of India. (2011). Primary Census Abstract: District Saharanpur, Uttar Pradesh. Office of the Registrar General and Census Commissioner, India. Census India.
- Census of India. (2011). District Census Handbook: Saharanpur, Uttar Pradesh. Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh. Census India
- Press Registrar General of India. (2023–24). Press in India. Government of India. Press Registrar General of India.
- Telecom Regulatory Authority of India. (2025). The Indian Telecom Services Performance Indicators / Yearly Report. Government of India. Telecom Regulatory Authority of India.

- World Bank. (2025). Rural Population (% of Total Population) – India. World Development Indicators. World Bank Open Data.
- United Nations Population Fund. (2025). India Population Data. United Nations Population Fund.

Cite the Article:

साक्षी, प्रो. प्रेमलता. (2026). ग्रामीण विकास एवं सामाजिक जागरूकता में प्रिंट मीडिया की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, 4(1) 255-264, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 04, Issue 01, September-2026., **DOI:** - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.29

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.